नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 075
दि. 17.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

बंगाल की मतदाता सूची में बड़ा फेरबदल, 58 लाख से ज्यादा नाम हटे, राजनीतिक हलकों में मचा घमासान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई, जब चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत राज्य की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की। इस सूची में 58 लाख 20 हजार 898 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। आंकड़ों के सामने आते ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से लेकर विपक्षी दलों तक में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इस बार हटाए गए नामों का असर सीधे बड़े नेताओं और प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ता नजर आ रहा है।

चुनाव आयोग के अनुसार, हटाए गए नामों में सबसे बड़ा हिस्सा उन मतदाताओं का है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे 'मृत' मतदाताओं की संख्या 24 लाख 16 हजार 852 बताई गई है। इसके अलावा 19 लाख 88 हजार 76 मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जो अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्रों में अब स्थायी रूप से नहीं रह रहे। 12 लाख 20 हजार 38 मतदाता अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले, जबकि 1 लाख 38 हजार 328 नाम ऐसे थे, जो मतदाता सूची में दो बार या फर्जी रूप से दर्ज पाए गए। इसके अलावा 57 हजार 604 नाम अन्य जटिलताओं और तकनीकी कारणों के आधार पर हटाने के प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं। आयोग ने साफ किया है कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वे फॉर्म-6 के जरिए

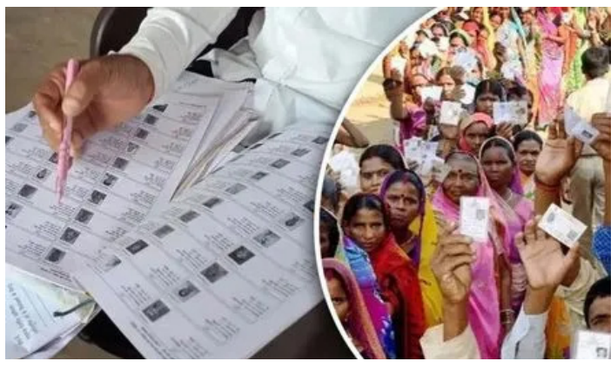

जरूरी दस्तावेजों के साथ दावा पेश कर सकते हैं।

इस व्यापक कवायद के तहत घर-घर जाकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब दावा, आपत्ति और सुनवाई का चरण शुरू होगा। एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। आयोग का अनुमान है कि अंतिम मसौदा सूची में 7 करोड़ 8 लाख 16 हजार 631 मतदाताओं के नाम हो सकते हैं।

मतदाता सूची में इस बड़े संशोधन का सबसे ज्यादा असर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिला है। पूरे राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक 74,553 नाम उत्तर कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए हैं, जहां से तृणमूल कांग्रेस की नयना बंद्योपाध्याय विधायक हैं। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम करते हैं, वहां से 63,730 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। टॉलीगंज से मंत्री आरूप विश्वास के क्षेत्र में 35,309, दमदम से शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के क्षेत्र में 33,862 और उत्तर दमदम से वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के क्षेत्र में 33,912 नाम काटे गए हैं। चंदननगर, जहां से मंत्री इंद्रनील सेन विधायक हैं, वहां 25,478 मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक गढ़ भवानीपुर में भी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। जनवरी 2025 में भवानीपुर में 2,06,295 मतदाता दर्ज थे, जिनमें से 44,787 नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए हैं। वहीं नंदीग्राम, जहां से 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था, वहां 2,78,212 मतदाताओं में से 10,599 नाम काटे गए हैं। इस तथ्य ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। जिला स्तर पर देखें तो सबसे अधिक 8,16,047 नाम दक्षिण 24 परगना जिले से हटाए गए हैं। मतदाता सूची में हुए इस बड़े बदलाव की तुलना बिहार से भी की जा रही है, जहां इसी साल की शुरुआत में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से बाहर कर दिए गए थे और उस पर भी राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध जताया था।

चुनाव आयोग का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि फर्जी, डुप्लिकेट और अपात्र नामों को हटाया जा सके। हालांकि, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के बड़े नेताओं और संवेदनशील सीटों पर बड़ी संख्या में नाम हटे हैं, उसने इस मुद्दे को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया है। आने वाले महीनों में जब दावा और आपत्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तब यह साफ होगा कि अंतिम मतदाता सूची का स्वरूप क्या होगा और इसका असर आगामी चुनावी समीकरणों पर किस तरह पड़ेगा।

जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरण में संसद को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, महाभियोग प्रक्रिया पर उठे संवैधानिक सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाते हुए लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के महासचिवों को नोटिस जारी किया है। यह मामला जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास में आग बुझाने के दौरान कथित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने और उसके बाद शुरू हुई महाभियोग प्रक्रिया से जुड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने इस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 7 जनवरी 2026 तय की है।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत न्यायाधीशों (जांच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत एक संसदीय समिति का गठन किया गया था। यह समिति उनके खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव की जांच कर रही है। जस्टिस वर्मा का तर्क है कि इस समिति का गठन असंवैधानिक है और संविधान के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करता है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। पीठ ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ-साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के महासचिवों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला न केवल एक व्यक्ति से जुड़ा है, बल्कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच संवैधानिक संतुलन से भी संबंधित है, इसलिए सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी।

जस्टिस वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में जोरदार दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में एक ही दिन पेश किया जाता है और स्वीकार किया जाता है, तो जांच समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। केवल लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति बनाना संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 तथा न्यायाधीशों (जांच) अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के विपरीत है। रोहतगी ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में संवैधानिक मर्यादाओं का पालन न किया जाना भविष्य में खतरनाक परंपरा बन सकता है।

यह पूरा मामला 14 मार्च की रात से जुड़ा है, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोररूम में आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान दमकल और पुलिस टीमों ने वहां जले हुए नोटों के बंडल मिलने का दावा किया था। इस घटना के बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश की ओर से तीन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि करते हुए जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया और संसदीय जांच समिति का गठन किया गया। अब इस पूरी प्रक्रिया को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि जांच और महाभियोग की कार्रवाई संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद के दोनों सदनों को नोटिस जारी किए जाने के बाद यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि अदालत इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और महाभियोग जैसी गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया की वैधता पर क्या दिशा-निर्देश देती है।

गोवा क्लब अग्निकांड के आरोपी भारत लौटे: थाइलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस ने दबोचा

(जीएनएस)। पणजी। गोवा के चर्चित नाइट क्लब अग्निकांड मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गए हैं। गोवा के 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद दोनों भाई देश छोड़कर थाइलैंड भाग गए थे। अब उन्हें थाइलैंड से भारत डिपोर्ट कर दिल्ली लाया गया है, जहां गोवा पुलिस की टीम ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

मंगलवार दोपहर करीब दो बजे दोनों भाई भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। जैसे ही वे एयरपोर्ट से बाहर निकले, पहले से मौजूद गोवा पुलिस की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस अब दोनों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश करेगी। रिमांड मिलने के बाद उन्हें गोवा ले जाया जाएगा, जहां इस मामले में आगे की जांच की जाएगी।

सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा गोवा के चर्चित बिर्च नाइट क्लब के मालिक हैं। छह दिसंबर को क्लब में

भीषण आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद दोनों भाई अचानक गायब हो गए थे, जिससे जांच एजेंसियों को शक हुआ कि वे देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। बाद में पुष्टि हुई कि दोनों थाइलैंड पहुंच गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, नौ दिसंबर को थाई अधिकारियों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिला कि जिन लूथरा ब्रदर्स की तलाश की जा रही है, वे फुकेट में छिपे हुए हैं। इसके बाद थाई पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारियों ने संभावित होटलों पर नजर रखना शुरू किया। 11 दिसंबर को जब दोनों भाई होटल से बाहर खाना खाने निकले, तो उनकी पहचान और यात्रा से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। सत्यापन के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

थाईलैंड में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों को भारत डिपोर्ट किया गया। गोवा पुलिस के अनुसार, लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और गंभीर लापरवाही के आरोप दर्ज किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आ रहा है कि क्लब में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी, जिसकी वजह से आग लगने की घटना इतनी भयावह साबित हुई।

गोवा क्लब अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटेंगी कि आग लगने के पीछे किन स्तरों पर लापरवाही हुई, किसकी जिम्मेदारी तय होती है और क्या इस मामले में अन्य लोग भी दोषी हैं। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए यह कार्रवाई एक अहम कदम मानी जा रही है।

मेसी कार्यक्रम की अव्यवस्था पर बड़ा राजनीतिक फैसला, बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने छोड़ा पद

(जीएनएस)। कोलकाता। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी के कार्यक्रम के दौरान मची अव्यवस्था और तोड़फोड़ के मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी लेते हुए राज्य के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने अपने पद से

इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 13 दिसंबर को हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे मंगलवार को स्वीकार कर लिया गया। नए खेल मंत्री की नियुक्ति होने तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं खेल विभाग का प्रभार संभालेंगी।

मुख्यमंत्री ने इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी सख्त कदम उठाए हैं। बिधाननगर के पुलिस कमिश्नर, राज्य के डीजीपी और खेल विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिन्हा को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। साथ ही मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि इस अव्यवस्था और सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके अलावा सॉल्ट लेक स्टेडियम यानी वीवाईबीके स्टेडियम के सीईओ डी.के. नंदन की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गई हैं। दरअसल, अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनल मेसी 13 दिसंबर को तीन दिवसीय भारत दौरे के तहत कोलकाता पहुंचे थे। इस दौरे को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह था। सुबह मेसी ने अपने 70 फीट ऊंचे स्टैच्यू का वर्चुअल उद्घाटन किया था, जबकि सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनके सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। योजना के अनुसार मेसी को स्टेडियम में लगभग एक घंटे तक रुकना था, लेकिन वे सिर्फ 22 मिनट में ही कार्यक्रम स्थल से लौट गए।

मेसी के अचानक चले जाने से हजारों की संख्या में मौजूद प्रशंसक नाराज हो गए। गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं और कई जगह तोड़फोड़ की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि भगदड़ जैसे दृश्य पैदा हो गए और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि किसी बड़े हादसे की खबर नहीं आई, लेकिन इस अव्यवस्था ने राज्य सरकार और प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी असहजता देखी गई। अंततः राजनीतिक जिम्मेदारी तय करते हुए खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा स्वीकार किया गया। अब सभी की निगाहें एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो सके कि इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय हस्ती के कार्यक्रम में ऐसी अव्यवस्था आखिर कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

कर्नाटक में किसान संकट गहराया: ढाई साल में 2800 से अधिक अन्नदाताओं ने तोड़ा दम

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या का संकट एक बार फिर गहरी चिंता का कारण बन गया है। वर्ष 2023-24 से अब तक राज्य में कुल 2,809 किसानों ने आत्महत्या की है, जिससे कर्नाटक देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में दूसरे स्थान

पर पहुंच गया है। यह जानकारी राज्य के कृषि मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने बेलगावी में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा विधायक अरविंद बेल्लाड के सवाल के लिखित जवाब में दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में 1,254 किसानों ने आत्महत्या की, 2024-25 में यह संख्या 1,178 रही, जबकि 2025-26 में अब तक 377 किसानों की आत्महत्या के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कृषि मंत्री ने सदन को बताया कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में मामलों में मामूली कमी जरूर आई है, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है।

जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो हावेरी जिला किसानों की आत्महत्या के मामलों में सबसे आगे है, जहां 297 किसानों ने अपनी जान दी। इसके बाद बेलगावी में 259, कलबुर्गी में 234, धारवाड़ में 195 और मैसुरु में 190 मामलों की पुष्टि हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य के कई हिस्सों में किसान लगातार आर्थिक दबाव, फसल नुकसान, कर्ज और अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार की ओर से आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। वर्ष 2023-24 में 1,081 पात्र परिवारों को कुल 54 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। इसी तरह 2024-25 में 896 परिवारों को 44.8 करोड़ रुपये, जबकि 2025-26 में नवंबर तक 193 परिवारों को 9.65 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद पहुंचाई गई है। इसके बावजूद राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि 112 मामलों की जांच और समीक्षा अभी लंबित है, जिन पर सरकारी स्तर पर प्रक्रिया जारी है। इन मामलों में पात्रता और कारणों की जांच के बाद सहायता देने का निर्णय लिया जाएगा। कर्नाटक में लगातार सामने आ रहे ये आंकड़े न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी गंभीर चेतावनी माने जा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने, कर्ज के बोझ से राहत देने और खेती को लाभकारी बनाने के तमाम दावों के बीच आत्महत्या के ये मामले जमीनी हकीकत को उजागर करते हैं। सवाल यह है कि क्या मौजूदा नीतियां किसानों को वास्तव में संकट से बाहर निकाल पा रही हैं, या फिर अन्नदाता अब भी व्यवस्था की अनदेखी का शिकार बना हुआ है।

संपादकीय

नफरती आतंकी हमलों से लड़े दुनिया

सिडनी में यहूदियों को निशाना बनाये जाने की घटना ने पहलगाम आतंकी हमले के जख्मों को हरा कर दिया। पहलगाम में भी आतंकियों ने लोगों को चुन-चुनकर मारा था। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय की सभा पर हुआ हमला हमें इस क्रूरता की याद दिलाता है कि आतंकवादी आम जीवन के केंद्र में, प्रार्थना स्थलों और सुकून देने वाले स्थलों को ही अपना निशाना बनाते हैं। यह हिंसा उस हनुक्का उत्सव के दौरान की गई, जो अंधकार के साम्राज्य को प्रकाश से पराजित करने का संकल्प दर्शाता है। इस मायने में यह हमला क्रूरता की हद दर्शाता है। दरअसल, आस्ट्रेलिया लंबे समय से इस विश्वास के चलते शांति का अहसास करता रहा है कि तमाम वैश्विक संघर्षों से बनायी गई उसकी दूरी, उसे सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन इस घटना के बाद उसका भ्रम टूटा है। अब जाकर उसे यह अहसास हुआ है कि आतंकवादी अपने घातक मसूंबों को अंजाम देने के लिये हमारे ऐसे ही विश्वासों को तोड़कर हमले करते हैं। बॉन्डी के हमले ने न केवल आस्ट्रेलिया के भ्रम को तोड़ा है बल्कि उसे अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव को बाध्य किया है। जैसा कि अपरिहार्य है, आस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने हमले को एक वैश्विक आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत किया है। खासकर हिंसा के तौर-तरीके और वैचारिक मकसद को ध्यान में रखते हुए। यह वर्गीकरण इस बात को भी स्वीकार करता है कि हमला नफरत से प्रेरित हिंसा के एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा था,जो दुनिया के तमाम देशों में देखा जा रहा है। इस आतंकी घटना के बाद यहूदी समुदाय में दुख के साथ-साथ आक्रोश भी उमड़ रहा है। खासकर इस बात को लेकर कि यहूदी समुदाय द्वारा लंबे समय से दी जा रही चेतावनी के बावजूद आस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी रवैये को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस प्रवृत्ति पर पहले से ही सतर्क निगरानी रखी गई होती तो शायद बॉन्डी के हमले को टाला जा सकता।

निस्संदेह, आस्ट्रेलिया में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। हालांकि, यहां हुए अधिकांश विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन चरमपंथी विचारधारा का पोषण करने वाले मुट्ठीभर लोग भी घातक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। यह हमला ऐसे मंसूबों की रोकथाम की सीमाओं को भी उजागर करता है। निस्संदेह, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से आंतकी नेटवर्क की निगरानी समय रहते की जा सकती है। वे सही वक्त पर ही न केवल आने वाले खतरों का आकलन कर सकती हैं बल्कि साजिशों को नाकाम भी कर सकती हैं। लेकिन एक विसंगति यह भी है कि सार्वजनिक स्थानों पर अकेले हमले करने वालों को रोकना कुछ कठिन जरूर होता है। जैसे कि इस मामले में देखने में आया है। फिर भी, इस भयावह घटना के बीच एक साहस देखने को भी मिला। एक बहादुर राहगीर ने एक हमलावर को निहत्था करने के लिये अपनी जान भी जोखिम में डाली। हालांकि, वह इस प्रयास में घायल हुआ, लेकिन वह कई लोगों की जान बचाने में कामयाब हुआ। पूरी दुनिया में उसके साहस के लिये प्रशंसा हो रही है। संकट की घड़ी में ऐसा साहस आतंकवादियों की कायरता पर करारा प्रहार होता है और इससे आतंकवादियों के मंसूबे धरे रह जाते हैं। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि घोर अंधकार के क्षणों में भी मानवता का अंत नहीं होता। निश्चित रूप से इस घटना के बाद आस्ट्रेलिया को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके यहां रह रहे संवेदनशील समुदायों के लिये मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही समय रहते समाज में घृणा को बढ़ाने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे वक्त में जब हमास व इस्राइल के संघर्ष के बाद पूरी दुनिया में यहूदी विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर साझा लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विश्व समुदाय को किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ होने वाली आतंकी घटनाओं का मुकाबला मिलकर करने की जरूरत है। अन्यथा कट्टरपंथी तत्वों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। इसके अलावा आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद, समर्थन व अन्य सहयोग देने वाले देशों पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है।

भारतीय आत्मनिर्भरता की आकांक्षा में रूस की अहम भूमिका

> रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से दोनों देशों में संबंध बेहतर हुए। इस दौरान रणनीतिक साझेदारी पर ज़ोर दिया। हालांकि इस मामले में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देना जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में सह-उत्पादन से सर्वाधिक फ़ायदा उठाने के लिए भारत को रूस के साथ साझेदारी नये सिरे से उन्मुख करने की जरूरत है। हालांकि इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नई दिल्ली का दो दिवसीय दौरा 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद भारत की उनकी पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में हुए इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच टिकाऊ रणनीतिक साझेदारी पर ज़ोर दिया गया, जिसे दशकों चले शीत युद्ध-काल के सहयोग के दौरान विकसित किया गया था।

इस यात्रा ने काफ़ी वैश्विक रुचि पैदा की, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ की कोशिश रही है कि यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति को 'अलग-थलग' किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने तो यूक्रेन में युद्ध अपराधों के संबंध में पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट तक जारी कर रखा है। इसलिए,उनकी अगवानी पारंपरिक शिखर सम्मेलन की भव्यता और संबंधित प्रोटोकॉल के साथ करने के भारतीय निर्णय का अपना रणनीतिक महत्व रहा।

मोदी ने हवाई अड्डे पर रूसी नेता का स्वागत ट्रेडमार्क बन चुके गले लगाने के अपने अंदाज़ में किया, जोकि दोनों नेताओं के बीच संबंध को रेखांकित करता है। यह यात्रा भारत पर रूसी तेल आयात और रक्षा खरीद पर अंकुश लगाने के लिए बढ़ते अमेरिकी दबावों के बीच हुई; दोनों पक्षों ने इस बात की पुष्टि की कि उनके संबंध 'बाहरी दबाव के परिप्रेक्ष्य में लचीले' हैं। 1960 के दशक के मध्य से रूस रिवायती तौर पर भारत को सैन्य उपकरण और प्रमुख युद्धक सामग्री (टैंक, जहाज, विमान) का आपूर्तिकर्ता रहा है, लेकिन यात्रा से पूर्व जताई गई उम्मीदों और अटकलों के विपरीत, पुतिन की यात्रा के दौरान कोई बड़ा रक्षा सौदा घोषित नहीं हुआ। संयुक्त बयान में संदर्भ अपेक्षाकृत सामान्य था और इसमें कहा गया था कि सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पारंपरिक रूप से भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का एक स्तंभ रहा है। आगे कहा गयाः 'भारत की आत्मनिर्भरता अभियान

के जवाब में,साझेदारी वर्तमान में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, सह-विकास और सह-उत्पादन की ओर फिर से उन्मुख हो रही है'।

ज्यादा ज़ोर भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए स्पेयर पार्ट्स, घटकों, संलग्न एवं अन्य उत्पादों के भारत में संयुक्त निर्माण पर दिया गया; भारतीय सशस्त्र बलों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करना; और आगे चलकर परस्पर मित्र तीसरे राष्ट्रों को निर्यात की तैयारी करना। मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन ने भारत-रूस रक्षा संबंधों में एक संभावित रणनीतिक बदलाव का संकेत दिया, जो पारंपरिक खरीदार-विक्रेता गतिशीलता से आगे बढ़कर प्रगाढ़ सहयोग की तरफ बढ़ रहा है। यह रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता पहल के अनुरूप है, जिसका मकसद आयात पर निर्भरता को और कम करना है – रूस की हिस्सेदारी 2010-15 के बीच 72 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर 2020-24 में 36 फीसदी रह गई। यह सबक लेने लायक है कि 1960 के दशक के मध्य में सोवियत संघ से काफी सैन्य साजो-सामान (पहला मिग फाइटर एयरक्राफ्ट, पेट्या/कमोर्टा-क्लास नौसैन्य पोत और टैंक) हासिल करने के बावजूद, भारत कभी भी अपने करीबी सहयोगी से कोई डिज़ाइन संबंधी जानकारी हासिल नहीं कर पाया। इस प्रकार, सोवियत/रूसी मूल के अधिकांश उपकरण जो कहने को तो भारत में 'निर्मित' किए गए थे, उनमें भी मुख्य रूप से काम आयातित किट/पुर्जों को असेंबल करने का ही था। इसका मतलब था कि चाहे वह गोला-बारूद फैक्ट्रियां हों या हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, मुख्य गतिविधि पुर्जों को जोड़ना भर था और रिवर्स-इंजीनियरिंग करने या स्वदेशी डिज़ाइन पर काम करने का बहुत कम या कोई प्रयास नहीं किया गया। डिज़ाइन के क्षेत्र में प्रवेश करने की यह अक्षमता/अनिच्छा चीनी उदाहरण के बिल्कुल विपरीत है।

सोवियत-युग के सैन्य उपकरणों की चीन की सबसे सफल रिवर्स-इंजीनियरिंग उपलब्धि एसयू-27 'फ्लैंकर' की नकल कर शेनयांग जे-11 फाइटर जेट परिवार का विकास करना है। पीएलए वायु सेना ने शुरू में 1990 के दशक में लाइसेंस प्राप्त उत्पादन समझौते के तहत रूस से एसयू-27 एसके फाइटर जेट खरीदे, और रूसी-आपूर्ति वाली किट का उपयोग करके उन्हें जे-11ए के रूप में असेंबल किया। हालांकि, 2000 के दशक के मध्य तक, चीन विमान की रिवर्स-इंजीनियरिंग करने में सफल रहा - प्रमुख घटकों को बाहर निकालकर, उनका विश्लेषण और नकल करके - बिना किसी और रूसी भागीदारी के पूरी तरह स्वदेशी जे-11बी संस्करण का उत्पादन कर लिया। इसमें एयरफ्रेम, एवियोनिक्स, राडार सिस्टम और प्रोपल्शन की नकल करना, फिर डब्ल्यूएस-10 टर्बोफैन इंजन (रूसी एएल-31एफ की रिवर्स-इंजी.), एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (एईएसए) राडार और घरेलू स्तर पर उत्पादित हथियार प्रणालियां जैसे कि चीनी अपग्रेड को एकीकृत करना शामिल था।

एसयू-27 खुद सोवियत संघ में बना था (1970 के दशक में डिज़ाइन किया गया, 1985 में सेवा में आया), जिससे जे-11 सोवियत तकनीक का सीधा रूपांतरण बन गया। इस डिज़ाइन सफलता ने चीन को अपनी आयात निर्भरता कम करने, आत्मनिर्भरता हासिल करने और फिर इस फाइटर का निर्यात करने के काबिल बनाया, जिसका एक प्रमुख खरीदार पाकिस्तान है। वहीं, भारत ने अपना पहला सुखोई, एसयू-30, 1997 में खरीदा, लेकिन मौजूदा राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र संकोची रहा और आयात निर्भरता जारी रही, जिसमें फ्रांसीसी लड़ाकू विमान (राफेल) एक वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। पुतिन की यात्रा में पांचवीं पीढ़ी के एसयू-57 फाइटर जेट में फिर से दिलचस्पी देखी गई, जिसमें भारत 'सोर्स कोड एक्सेस' और 'स्टेल्थ एन्हांसमेंट' तकनीक हस्तांतरण की मांग कर रहा है। क्या यह बतौर संभावित अधिग्रहण स्वदेशी तेजस का पूरक बनेगा, यह बहस का मुद्दा बना हुआ है।

इससे इनकार नहीं कर सकते कि रूस (सोवियत युग के दौरान और उसके बाद भी) ने भारत को कुछ खास क्षेत्रों में अमूल्य तकनीकी सहायता प्रदान की है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है - मिसाइलें और पानी के नीचे परमाणु चलित पनडुब्बी (आईएनएस अरिहंत) इसकी मिसाल हैं। संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस मिसाइल एक सफलता गाथा है, और इस यात्रा में इस मिसाइल के हल्के वेरिएंट को सहयोग के संभावित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अहम सैन्य उपकरणों का डिज़ाइन ज्ञान किसी राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण है और ऐसा ज्ञान बाजार से आसानी से नहीं खरीदा जा सकता। सोवियत संघ/रूस, जिससे भारत के मजबूत सैन्य आपूर्तिकर्ता संबंध रहे हैं, उसने भी डिज़ाइन ज्ञान साझा नहीं किया है।

पुतिन की यात्रा के परिणाम बढ़िया हो सकते हैं बशर्ते भारत आत्मनिर्भरता को उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ प्राथमिकता दे पाए और रूस के साथ साझेदारी की ओर फिर से उन्मुख होकर चुनिंदा उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, सह-विकास और सह-उत्पादन की पूरी क्षमता का अहसास कर पाए। लेकिन यह कठिन यात्रा होगी और इसके लिए भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में निहित बाधाओं को दूर करना होगा होगा। हालांकि रूस के लिए भी कुछ लाल लकीरें हैं, कि भारत के साथ सैन्य सहयोग कितना प्रगाढ़ रखा जाए और इस बाबत रूस चीन की चिंता कैसे दूर करेगा। इसी प्रकार, भारत को रूस के साथ जुड़ाव को लेकर अमेरिका के कड़े नियमों को ध्यान में रखना होगा।

पुतिन की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन दोनों देशों के लिए नई चुनौतियां उभर रही हैं।

प्रेरणा

प्रेम की राह पर लौटता मनुष्य

एक शांत संध्या का समय था। जंगल के किनारे बनी एक छोटी-सी कुटिया के पास एक गड़रिया बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी शांति और अनोखी प्रसन्नता झलक रही थी। उसने अपने कंधे से एक भेड़ को बड़े स्नेह से नीचे उतारा। वह भेड़ थकी हुई थी, उसके पैरों पर जंगल की कांटेदार झाड़ियों के निशान थे। गड़रिए ने पहले उसे पानी से स्नान कराया, फिर अपने पुराने कपड़े से उसके गीले बालों को धीरे-धीरे सुखाया। उसके हाथों में कोई जल्दबाज़ी नहीं थी, केवल अपनापन था। थोड़ी देर बाद उसने उसे हरी-हरी घास खिलाई, जिसे खाते हुए भेड़ बार-बार उसकी ओर भरोसे से देख रही थी।

उसी कुटिया के पास महापुरुष ईसा विश्राम कर रहे थे। उन्होंने गड़रिए के चेहरे पर छाई खुशी और भेड़ के प्रति उसके स्नेह को ध्यान से देखा। ईसा ने मुस्कराते हुए उससे पूछा, "वत्स, आज तुम्हारे चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता क्यों है? क्या कोई विशेष कारण है?"

गड़रिए ने विनम्रता से उत्तर दिया, "महात्मन, यह भेड़ बार-बार जंगल में भटक जाती थी। रास्ता भूल जाती थी,

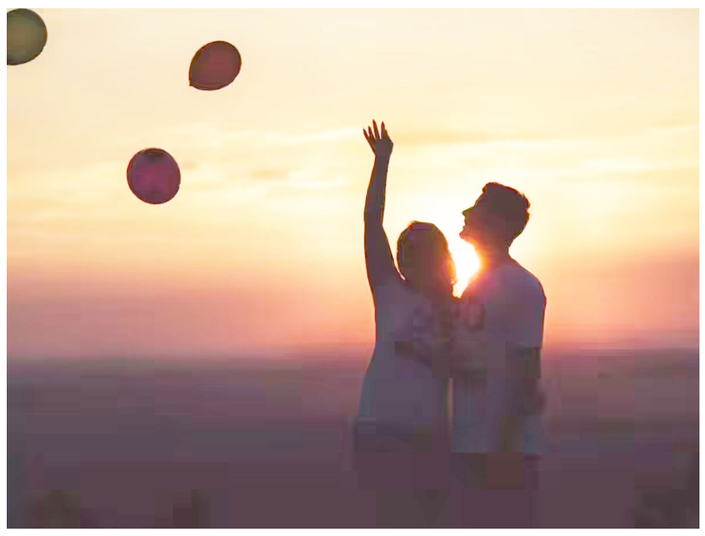

कभी भय से काँपती हुई मिलती थी तो कभी घायल अवस्था में। मेरे पास और भी कई भेड़ें हैं, वे बिना रुके सीधे घर लौट आती हैं, लेकिन यह नहीं लौट पाती। आज जब इसे फिर से सुरक्षित वापस लाया, तो मन को बड़ा संतोष मिला। मैंने इसे प्यार इसलिए दिया ताकि इसके मन से डर निकल जाए और यह फिर रास्ता न भूले।"

ईसा यह सुनकर कुछ पल मौन रहे। उनकी दृष्टि में गहरी करुणा उतर आई। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, "यही जीवन का सत्य है। जो अपनी राह से भटक जाते हैं, जो भूलवश या अज्ञान में गलत मार्ग पर चले जाते हैं, उन्हें कठोर शब्दों या दंड से नहीं, बल्कि प्रेम और समझ से ही सही दिशा दी जा सकती है। जिस प्रकार यह भेड़ डर और थकान के कारण भटक गई थी, उसी प्रकार मनुष्य भी दुख, भय और मोह के कारण मार्ग से दूर हो जाता है।"

ईसा आगे बोले, "यदि गड़रिया इस भेड़ को मारता, डाँटता या ठुकरा देता, तो यह और दूर भाग जाती। लेकिन प्रेम ने इसे रोक लिया, स्नेह ने इसे वापस मोड़ दिया। मनुष्य का हृदय भी ऐसा ही है—जहाँ प्रेम मिलता है, वहाँ वह झुक जाता है, सुधर जाता है और लौट आता है।"

उस शांत वातावरण में गड़रिए ने ईसा की बातों को सुना और उसके मन में भी यह भाव और गहरा हो गया कि प्रेम केवल भेड़ों को नहीं, बल्कि हर भटके हुए मनुष्य को उसकी मंज़िल तक पहुँचा सकता है। उस दिन जंगल के उस कोने में यह संदेश गूँज उठा कि रास्ता भले ही कितना ही बिगड़ जाए, प्रेम की एक किरण उसे फिर से उजाला दिखा सकती है।

Tamilnadu Elections के लिए BJP ने बिछाई गजब की चौसर, अनुभवी मोहरों को मैदान में उतार कर विरोधियों की मुश्किलें भी बढ़ाईं

तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज़ कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि भाजपा का अगला लक्ष्य तमिलनाडु है। इसके बाद पार्टी ने राज्य में संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में भाजपा ने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक बार फिर तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल को सह-प्रभारी बनाया गया है। यह नियुक्तियाँ इस बात का संकेत हैं कि भाजपा राज्य में आगामी चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। हम आपको याद दिला दें कि पीयूष गोयल पहले भी 2019 के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु के प्रभारी रह चुके हैं और उस समय उन्होंने भाजपा तथा अन्नाद्रमुक (AIADMK) के बीच गठबंधन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी। अन्नाद्रमुक के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) को एक सख़्त और कुशल वार्ताकार माना जाता है और ऐसे में गोयल का अनुभव भाजपा के लिए उपयोगी माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, गोयल सीट बंटवारे के साथ-साथ गठबंधन से जुड़े अन्य संवेदनशील मुद्दों पर भी ईपीएस से बातचीत करेंगे।

हम आपको यह भी बता दें कि भाजपा इस समय अन्नाद्रमुक पर यह दबाव बना रही है कि वह ओ. पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) और टी.टी.वी. दिनाकरन जैसे विद्रोही नेताओं को कम से कम एनडीए के सहयोगी के रूप में स्वीकार करे। ईपीएस इन नेताओं को दोबारा अन्नाद्रमुक में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन भाजपा का मानना है कि इन्हें एनडीए से बाहर रखना मुकुलथोर समुदाय के मतदाताओं को दूर कर सकता है, जिसका नुकसान सीधे-सीधे भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन को होगा। सूत्रों के मुताबिक, ओपीएस ने हाल की बैठकों में भाजपा नेतृत्व को यह भरोसा दिलाया है कि वह फरवरी तक किसी अन्य राजनीतिक विकल्प की ओर नहीं जाएंगे। वहीं टीटीवी दिनाकरन का रुख अधिक आक्रामक माना जा रहा है, क्योंकि वह ईपीएस के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। भाजपा नेतृत्व आने वाले हफ्तों में दिनाकरन से भी संपर्क साधने की योजना बना रहा है, ताकि मुकुलथोर वोटों का विभाजन रोका जा सके। भाजपा ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह 2026 के विधानसभा चुनाव में पहले की तुलना में अधिक सीटों की मांग करेगी। पार्टी का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उसे लगभग 11 प्रतिशत वोट शेयर मिला था और पूरे एनडीए को करीब 18 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। ऐसे में भाजपा 2021 की तरह 20 सीटों पर संतोष नहीं करेगी। पार्टी ने लगभग 50 सीटें अपने लिए और 15 सीटें 'मैत्रीपूर्ण सहयोगियों' के लिए चिन्हित की हैं, जिन पर कमल के चुनाव चिह्न पर उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं।

इसी बीच, भाजपा ने असम के लिए भी संगठनात्मक नियुक्तियाँ की हैं। वरिष्ठ नेता बैजयंत पांडा को असम का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पांडा इससे पहले 2021 के असम विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता में वापस लाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। यह नियुक्तियाँ यह दर्शाती हैं कि भाजपा चुनावी प्रबंधन में अनुभवी और भरोसेमंद नेताओं पर दांव लगा रही है।

देखा जाये तो तमिलनाडु लंबे समय से भाजपा के लिए एक कठिन राजनीतिक मैदान रहा है। द्रविड़ राजनीति की गहरी जड़ें, भाषा और सांस्कृतिक पहचान का सवाल तथा डीएमके-अन्नाद्रमुक की पारंपरिक पकड़, इन सबके बीच भाजपा को अब तक सीमित सफलता ही मिली है। लेकिन हालिया घटनाक्रम यह संकेत देता है कि भाजपा इस बार केवल "सहयोगी की भूमिका" में नहीं रहना चाहती, बल्कि राज्य की राजनीति में निर्णायक हस्तक्षेप करने की रणनीति पर काम कर रही है।

पीयूष गोयल की पुनर्नियुक्ति महज़ सामान्य राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि यह भाजपा की रणनीतिक सोच को दर्शाता है। पीयूष गोयल न केवल एक अनुभवी मंत्री हैं, बल्कि जटिल गठबंधनों को संभालने में भी माहिर माने जाते हैं। उनकी शांत लेकिन दृढ़ कार्यशैली ईपीएस जैसे नेताओं से बातचीत में संतुलन बना सकती है। वहीं अर्जुन मेघवाल का संगठनात्मक अनुभव और संसदीय समझ तथा मुरलीधर मोहोल की युवा ऊर्जा और जमीनी संपर्क क्षमता इस टीम को और मज़बूत बनाती है। वहीं असम में बैजयंत पांडा की भूमिका भाजपा की उस रणनीति का उदाहरण है, जिसमें चुनावी प्रबंधन को एक पेशेवर कौशल के रूप में देखा जाता है। हम आपको याद दिला दें कि पांडा ने पहले भी साबित किया है कि वह संगठन, सरकार और सहयोगी दलों के बीच समन्वय स्थापित करने में सक्षम हैं। यह मॉडल अब तमिलनाडु में भी लागू किया जा रहा है। तमिलनाडु में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह खुद को केवल अन्नाद्रमुक की "जूनियर पार्टनर" छवि से बाहर निकाले। अधिक सीटों की मांग और अलग पहचान बनाने की कोशिश इसी दिशा में उठाया गया कदम है। यदि भाजपा ओपीएस और टीटीवी जैसे नेताओं को एनडीए में बनाए रखने में सफल होती है, तो यह न केवल सामाजिक संतुलन को साधेगा बल्कि डीएमके के खिलाफ एक व्यापक मोर्चा भी तैयार करेगा।

बहरहाल, भविष्य की राजनीति के लिहाज़ से देखें तो भाजपा तमिलनाडु में धीरे-धीरे एक वैकल्पिक ध्रुव बनाना चाहती है। संगठनात्मक विस्तार, नेतृत्व में विविधता और राष्ट्रीय स्तर की जीतों, जैसे बिहार में एनडीए की हालिया सफलता, का हवाला देकर पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल उत्तर भारत की पार्टी नहीं रही। यदि यह रणनीति ज़मीन पर असर दिखाती है, तो आने वाले वर्षों में तमिलनाडु की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर सकती है, जहां भाजपा केवल दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी होगी।

अभियान

जीवन को सफल बनाने वाली साधना

भारतीय सनातन परंपरा में पर्व और तिथियाँ केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होतीं, वे मनुष्य के जीवन को भीतर से संस्कारित करने का माध्यम होती हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी भी ऐसी ही एक पावन तिथि है, जो भक्ति, संयम और आत्मिक शुद्धि का गहरा भाव अपने भीतर समेटे हुए है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना का है, पर साथ ही यह मनुष्य को अपने विचारों, इच्छाओं और आचरण को परिष्कृत करने का अवसर भी देता है।

एकादशी का व्रत भारतीय जीवन-दर्शन में आत्मनियंत्रण की साधना माना गया है। वर्ष में आने वाली चौबीस एकादशियों में सफला एकादशी को इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि यह जीवन के असंतुलन को संतुलन में बदलने की प्रेरणा देती है। लोकविश्वास है कि इस दिन किया गया व्रत संकटों से रक्षा करता है और साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। 'सफला' शब्द स्वयं यह संकेत देता है कि यह तिथि मनुष्य के प्रयासों को सार्थक दिशा देती है और उसे आत्मिक

उन्नति की ओर अग्रसर करती है।

योगशास्त्र के अनुसार एकादशी तिथि मन को शांत और स्थिर करने के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। चंद्रमा से जुड़ी होने के कारण इस दिन मन सहज रूप से संयम की ओर झुकता है। जब भोजन में संयम रखा जाता है और इंद्रियों को विश्राम दिया जाता है, तब भीतर की ऊर्जा जागृत होने लगती है। ध्यान, जप और प्रार्थना का प्रभाव इस दिन अधिक गहराई से अनुभव किया जाता है। तामसिक भोजन का त्याग और सात्त्विक जीवनशैली का अभ्यास मनुष्य को भीतर से हल्का और निर्मल बनाता है।

सफला एकादशी का महत्व केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है। यह तिथि सामाजिक चेतना को भी जागृत करती है। इस दिन दान-पुण्य की परंपरा समाज में करुणा और सह-अस्तित्व के भाव को मजबूत करती है। अन्न, फल, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान जरूरतमंदों तक संवेदना पहुँचाने का माध्यम बनता है। भजन, कीर्तन और सत्संग लोगों को आपस में जोड़ते हैं और सामूहिक भक्ति का वातावरण निर्मित करते हैं। किसान और व्यापारी इस दिन नए कार्यों और संकल्पों का आरंभ करते हैं, क्योंकि यह तिथि शुभता और सफलता का प्रतीक मानी जाती है।

सफला एकादशी से जुड़ी कथा इसके आध्यात्मिक संदेश को अत्यंत सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। राजा महिष्मति का पुत्र लुबंक अपने अनाचरण और उद्दंड स्वभाव के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। जंगल में भटकते हुए उसका जीवन धीरे-धीरे अधर्म और अपराध की ओर बढ़ने लगा। एक दिन भीषण ठंड में, भूख और असहाय अवस्था में, वह एक वृक्ष के नीचे बैठा रहा। उसके पास न भोजन था, न शरण। अनजाने में उसने एकादशी का पूर्ण उपवास कर लिया। अगले दिन जो थोड़े-से फल उसे मिले, उन्हें उसने उसी वृक्ष के नीचे रख दिया और विश्राम करने लगा। उसकी यह सरल, निष्कपट और अहंकाररहित अवस्था भगवान विष्णु को प्रिय हो गई। इस अनजाने व्रत और निर्मल भाव का प्रभाव लुबंक के जीवन में गहरे परिवर्तन के रूप में प्रकट हुआ। उसके भीतर पश्चाताप जागा, मन शुद्ध हुआ और आचरण में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। अंततः वह अपने पूर्व कर्मों से मुक्त होकर पुनः राज्य में लौटा और एक योग्य शासक बना। यह कथा बताती है कि ईश्वर की कृपा के लिए आडंबर या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि शुद्ध मन और सच्चा भाव ही सबसे बड़ा साधन है।

सफला एकादशी का यही मूल संदेश है कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप बाहरी कर्मकांड में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और आचरण की पवित्रता में निहित है। यह तिथि मनुष्य को सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण, संयम और करुणा ही अध्यात्म की सच्ची पहचान हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेता है, तभी उसका जीवन वास्तव में सफल बनता है। इसी भाव में सफला एकादशी एक व्रत मात्र नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली साधना बन जाती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात की राष्ट्रीय उपलब्धि

- ‘ग्रीन योर स्कूल प्रोग्राम’ के अंतर्गत गांधीनगर के जीवराजना मुवाड़ा प्राथमिक स्कूल को मिला राष्ट्रीय स्तर का ‘ग्रीन स्कूल अवॉर्ड-2025’
- देशभर के 720 स्कूलों में से गुजरात के सरकारी प्राथमिक स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया
- मुंबई में आयोजित ‘इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस’ में अवॉर्ड दिया गया
- ग्रीन स्कूल से जुड़े 11 नए विचारों-प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए विशेष सम्मान
- विभिन्न प्रकार के लगभग 1,200 से अधिक वृक्षों से स्कूल का ग्रीन कैंपस सुसज्जित

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गांधीनगर जिले के जीवराजना मुवाडा गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के साथ ही शिक्षा क्षेत्र में केवल जिले का ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य का गौरव बढ़ाया है। मुंबई में इन्डियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ‘ग्रीन योर स्कूल प्रोग्राम’ के अंतर्गत गांधीनगर के जीवराजना मुवाडा प्राथमिक स्कूल को राष्ट्रीय स्तर का ‘ग्रीन स्कूल अवॉर्ड-2025’ दिया है। लगभग 1,200 से अधिक वृक्षों वाले इस स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन स्कूल से संबंधित 11 नए विचारों तथा प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए 3 लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया है।

केंद्र सरकार के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तथा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के संयुक्त उपक्रम से नवंबर-2025 में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन किया गया। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा हर वर्ष ‘ग्रीन योर स्कूल प्रोग्राम’ के अंतर्गत देश भर से स्कूलों के पंजीकरण आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें इस वर्ष देश से 720 स्कूलों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की थी, जिनमें से प्रथम तीन स्थान पर गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी के स्कूलों का चयन किया गया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 26 नवंबर, 2025 को गुजरात सहित तीन स्कूलों द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूशन, मुंबई में जूरी के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया। राज्य के समग्र शिक्षा विभाग, स्कूल के प्रधानाचार्य श्री बिपिन गोस्वामी तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किए गए ग्रीन स्कूल से संबंधित 11 नए विचारों और स्कूल में चल रहे प्रोजेक्ट पर देहगाम तहसील के जीवराजना मुवाड़ा प्राथमिक स्कूल के छात्रों; श्री मीत ठाकोर, श्री यामी ठाकोर और श्री जिग्नेश झाला द्वारा जूरी के समक्ष प्रभावी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

इस ग्रीन अवॉर्ड के लिए स्कूल द्वारा कुल 11 आईडिया दिए गए थे, जिनमें होम मेड जीवामृत, पेपर रिसाइक्लिंग, मूड पेंटिंग, अर्थन पॉट एसी विद होममेड, पोर्टेबल बायोगैस प्लांट, प्लास्टिक फ्री स्कूल, स्मार्ट एनर्जी ऑडिट, ग्रे वाटर सिस्टम, सोलर वोटर पंप, नेकी की दीवार, रेड बुक डेटा जैसे विचार शामिल हैं, जिनका आगामी समय में क्रियान्वयन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त स्कूल में ऊर्जा, पानी तथा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल में ‘फ्री प्लास्टिक स्कूल, फ्री प्लास्टिक विलेज’ पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 में क्लाइमेट चेंज का अवॉर्ड भी इस स्कूल को प्रदान किया गया था। बच्चे स्कूल में चॉकलेट की जगह छोटा पौधा भेंट करते हैं और जब तक वे पढ़ते हैं, तब तक उसका संरक्षण भी स्कूल के बच्चों द्वारा किया जाता हैं। स्कूल में विभिन्न वेस्ट वस्तुओं से फाइटर प्लेन, सैटेलाइट, पवन चक्की, पृथ्वी का गोलाकार मॉडल (ग्लोब), हाइड्रोपोनिक सिस्टम जैसे अनेक नवीन मॉडल बनाए गए हैं। इसके साथ ही बटरफ्लाई गार्डन की देखभाल तथा किचन गार्डन जैसी सर्जनात्मक प्रवृतियां कर छोटे छात्रों ने शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

किसान संगठन के अग्रणियों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से की मुलाकात

किसान हितैषी दृष्टिकोण के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में हुई बेमौसम और असाधारण बारिश की स्थिति में किसानों के साथ खड़े रहकर 10 हजार करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने वाले प्रभावित किसानों को अब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए 5300 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस किसान हितकारी दृष्टिकोण के लिए राज्य की विभिन्न खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समितियों (एपीएमसी), मार्केट यार्ड और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को गांधनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। इतना ही नहीं, मूंगफली सहित विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी कर राज्य सरकार किसानों हिमायती बनी है।

ऐसे किसान हितैषी कदमों और त्वरित निर्णयों से किसी भी आपदा की घड़ी में धरतीपुत्रों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और राज्य सरकार सदैव संवेदनशील रही है, इसके लिए भी किसान अग्रणियों ने राज्य के किसानों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, मंत्री सर्वश्री ऋषिकेशभाई पटेल, कुंवरजीभाई बावळिया, नरेशभाई पटेल, अर्जुनभाई मोढवाडिया और डॉ. प्रद्युमन वाजा भी उपस्थित रहे।

आणंद – गोधरा सेक्शन पर स्पीड बढ़ाकर 110 किमी प्रति घंटा की गयी

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल द्वारा आणंद -गोधरा सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम अनुमत स्पीड को सफलतापूर्वक बढ़ाकर 110 किमी प्रति घंटा कर दिया गया है। इससे रेल खंड की सेक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और समय की बचत होने से यात्रियों का सफ़र अधिक आरामदायक होगा।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आणंद -गोधरा सेक्शन की कुल लंबाई 78 किलोमीटर है। सेक्शन पर यात्री यातायात शुरु होने पर अप लाइन पर स्पीड लिमिट लगाई गई थी। सेक्शन में स्पीड अपग्रेडेशन करने के लिए बैलास्ट प्रोफाइल में व्यवस्थित सुधार किया गया और साथ ही कुछ पुलों को और मजबूत किया गया। यह पहल वडोदरा मंडल की आधुनिक रखरखाव तरीकों को अपनाने और बेहतर परिचालन दक्षता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्पीड अपग्रेडेशन से यात्रियों को इस महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर पर यात्रा के समय में कमी, ट्रेनों के सुचारू संचालन और सेवाओं की बेहतर विश्वसनीयता का लाभ मिलेगा। वडोदरा मंडल यात्रिओं को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक रेल सेवाएं प्रदान करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिकीकरण और सुरक्षा-उन्मुख कार्यों को जारी रखने के लिए प्रतिबध्द है।

पश्चिम रेलवे वलसाड एवं वेलांकन्नि के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से वलसाड एवं वेलांकन्नि स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 09047/09048 वलसाड – वेलांकन्नि स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09047 वलसाड–वेलांकन्नि स्पेशल वलसाड से शनिवार, 20 दिसंबर, 2025 को 17.45 बजे प्रस्थान करेगी तथा सोमवार को 07.30 बजे वेलांकन्नि पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09048 वेलांकन्नि – वलसाड स्पेशल वेलांकन्नि से सोमवार, 22 दिसंबर, 2025 को 22.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा बुधवार 13.30 बजे वलसाड पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वापी, वसई रोड, कल्याण, लोनावला, पुणे, सोलापुर, कलबुर्गि, वाडी, यादगिर, कृष्णा, रायचूर, मंत्रालयम रोड, अदोनि, गुंतकल, गूटी, ताडिपत्रि, यर्रगुंटला, कडप्पा, राजमपेटा, रेणिगुंटा, काटपाडी, तिरुवण्णामलै, विल्लुपुरम, कडलूर पोर्ट, चिदम्बरम, मयिलाडुतुरै, कारैक्काल, नागूर और नागप्पट्टिनम स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09047 की बुकिंग 18 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

एमसीएक्स पर सोना वायदा 582 रुपये और चांदी वायदा 1144 रुपये लुढ़काः क्रूड ऑयल वायदा 61 रुपये फिसला

कमोडिटी वायदाओं में 33400.55 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 189286.14 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 27335.23 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 32590 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 222690.4 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 33400.55 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 189286.14 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 32590 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2280.99 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 27335.23 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 133523 रुपये के भाव पर खूलकर, 134094 रुपये के दिन के उच्च और 133308 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 134130 रुपये के पिछले बंद के सामने 582 रुपये या 0.43 फीसदी की गिरावट के साथ 133548 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 403 रुपये या 0.38 फीसदी लुढ़ककर 106900 रुपये प्रति 8 ग्राम बोला गया। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 55 रुपये या 0.41 फीसदी लुढ़ककर 13383 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 132350 रुपये के भाव पर खूलकर, 132420 रुपये के दिन के उच्च और 131663 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 571 रुपये या 0.43 फीसदी लुढ़ककर 131920 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 132500 रुपये के भाव पर खूलकर, 132764 रुपये के दिन के उच्च और 132000 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 132802 रुपये के पिछले बंद के सामने 485 रुपये या 0.37 फीसदी लुढ़ककर 132317 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 195056 रुपये के भाव पर खूलकर, 197708 रुपये के दिन के उच्च और 194260 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 197901 रुपये के पिछले बंद के सामने

1144 रुपये या 0.58 फीसदी लुढ़ककर 196757 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1154 रुपये या 0.58 फीसदी गिरकर 197317 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1118 रुपये या 0.56 फीसदी घटकर 197330 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 3094.12 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 2 रुपये या 0.18 फीसदी गिरकर 1107.7 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 4 रुपये या 1.3 फीसदी गिरकर 304.7 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 1.1 रुपये या 0.39 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 281.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 10 पैसे या 0.06 फीसदी के सुधार के साथ 181.35 रुपये प्रति किलो बोला गया। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2998.92 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 5149 रुपये के भाव पर खूलकर, 5154 रुपये के दिन के उच्च और 5074 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 61 रुपये या 1.19 फीसदी गिरकर 5081 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 64 रुपये या 1.24 फीसदी की गिरावट के साथ 5081 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 365.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 365.6 रुपये के दिन के उच्च और 353.5 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 369.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 12.1 रुपये या 3.27 फीसदी लुढ़ककर 357.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 12.1 रुपये या 3.27 फीसदी गिरकर 357.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 933 रुपये पर खूलकर, 17.1 रुपये या 1.84 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 945.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 12679.33 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 14655.90 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2199.54 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 200.49 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 46.59 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 647.50 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 712.72 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2276.56 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 15770 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 72576 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20047 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 329334 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 34694 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 16605 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40459 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 115366 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 24537 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 41301 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा 32500 पॉइंट पर खूलकर, 32640 के उच्च और 32415 के नीचले स्तर को छूकर, 211 पॉइंट घटकर 32590 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल दिसंबर 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 42.2 रुपये की गिरावट के साथ 30.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 7.2 रुपये की गिरावट के साथ 13.25 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 138000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 225 रुपये की गिरावट के साथ 740 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 845.5 रुपये की गिरावट के साथ 4248.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.3 रुपये की गिरावट के साथ 10.75 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.53 रुपये की गिरावट के साथ 1 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल दिसंबर 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 16.1 रुपये की बढ़त के साथ 46.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.7 रुपये की बढ़त के साथ 15.35 रुपये हुआ।

इसके सामने चांदी दिसंबर 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 100.5 रुपये की बढ़त के साथ 1015 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 56 पैसे के सुधार के साथ 12.72 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.07 रुपये की बढ़त के साथ 2.6 रुपये हुआ।

यात्रियों की सुविधा हेतु कुछ ट्रेनों के समय में संशोधन

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा एवं ट्रेनों की समयपालन क्षमता में सुधार के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल से संबंधित कुछ ट्रेनों के समय में संशोधन किया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह संशोधित समयसारणी 22 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगी।

प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैंः

1. ट्रेन संख्या 59561 राजकोट–पोरबंदर के राजकोट से प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है तथा मार्ग के विभिन्न स्टेशनों पर आगमन/प्रस्थान समय संशोधित किए गए हैं। पोरबंदर पर आगमन समय पूर्ववत रहेगा। यह ट्रेन राजकोट से 08.35 बजे की बजाय 08.50 बजे प्रस्थान करेगी।

2. ट्रेन संख्या 59422 वेरावल–राजकोट के वेरावल से रीबडा स्टेशन तक समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल भक्तिनगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है। इस ट्रेन

का भक्तिनगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय क्रमशः 09.17/09.18 बजे की बजाय 09.04/09.06 बजे रहेगा।

3. ट्रेन संख्या 19207 पोरबंदर–राजकोट के वेरावल से गोंडल तक समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भक्तिनगर स्टेशन पर समय संशोधित किया गया है। इस ट्रेन का भक्तिनगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय क्रमशः 10.00/10.01 बजे की बजाय 09.50/09.52 बजे रहेगा।

4. ट्रेन संख्या 59423 राजकोट–वेरावल के राजकोट से प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है तथा भक्तिनगर स्टेशन पर संशोधित समय लागू होगा। आगे वेरावल तक समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह ट्रेन राजकोट से 08.00 बजे की बजाय 07.55 बजे प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का भक्तिनगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय क्रमशः 08.12/08.14 बजे की बजाय 08.07/08.09 बजे रहेगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व संबंधित ट्रेन का संशोधित समय रेलवे पूछताछ, अधिकृत रेलवे वेबसाइट अथवा निकटतम रेलवे स्टेशन से अवश्य जांच लें।

भारत के एआई और हेल्थ सेक्टर में बड़ा निवेशः गूगल देगा 8.4 मिलियन डॉलर, स्वदेशी मॉडल और भाषाई तकनीक को मिलेगी मजबूती

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने देश में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने और स्वास्थ्य मॉडल के विकास को गति देने के लिए कुल 8.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस निवेश का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और टिकाऊ शहरों से जुड़े एआई उत्कृष्टता केंद्रों के विकास के साथ-साथ भारत-विशिष्ट स्वास्थ्य समाधान तैयार करने में किया जाएगा। गूगल की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कंपनी भारत में बहुभाषी और समावेशी एआई तकनीक को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि तकनीकी प्रगति का लाभ देश के हर वर्ग और हर भाषा तक पहुंच सके। इसी उद्देश्य के तहत स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में एआई आधारित अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए वधवानी एआई को 45 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा भारतीय भाषाओं पर केंद्रित एआई समाधान तैयार करने के लिए ज्ञानीडॉटएआई, कोरोवरडॉटएआई और भारतजेन को 50-50 हजार अमेरिकी डॉलर का अनुदान देने का फैसला किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर गूगल का फोकस खास तौर पर भारत की जरूरतों के अनुरूप एआई मॉडल तैयार करने पर है। कंपनी ने भारत के स्वास्थ्य मॉडल के विकास में सहयोग के लिए चार लाख अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। इस पहल के तहत ‘मेडगेम्मा’ तकनीक का उपयोग करते हुए नए सहयोग शुरू किए जाएंगे। अजना लैंस और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विशेषज्ञ मिलकर त्वचा रोग विज्ञान और ओपीडी ट्राइएजिंग के लिए भारत-विशिष्ट एआई मॉडल विकसित करेंगे, जिससे मरीजों की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण और इलाज की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के शोधकर्ता और चिकित्सक एआई के व्यापक नैदानिक उपयोग की संभावनाओं पर काम करेंगे, ताकि तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार हो सके।

गूगल ने भारतीय भाषाओं और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मुंबई को भी बड़ी सहायता देने की घोषणा की है। कंपनी आईआईटी मुंबई में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक योगदान देगी। गूगल का कहना है कि इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एआई में हो रही वैश्विक प्रगति भारत की भाषाई विविधता के अनुरूप हो और देश के सामाजिक व आर्थिक हितों को मजबूती मिले।

विकसित बिहार की दिशा में बड़ा कदमः नीतीश कैबिनेट से ‘सात निश्चय-3’ को हरी झंडी, रोजगार से निवेश तक बदलेगा राज्य का चेहरा

(जीएनएस)। पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी विकास योजना ‘सात निश्चय-3’ को मंजूरी दे दी गई। सरकार का कहना है कि इस योजना का मूल उद्देश्य अगले पांच वर्षों में बिहार को देश के विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है। कैबिनेट की स्वीकृति के साथ ही यह साफ हो गया है कि सरकार अब विकास, रोजगार और निवेश को केंद्र में रखकर बड़े स्तर पर नीतिगत और संरचनात्मक बदलाव करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के बाद बताया कि सात निश्चय-3 के तहत युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की योजनाओं को भी व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

सरकार ने औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करने की रूपरेखा भी तैयार की है। सात निश्चय-3 के तहत करीब 50 लाख करोड़ रुपये तक के निजी निवेश को बिहार में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए औद्योगिक नीतियों को सरल बनाने, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और निवेशकों को अनुकूल माहौल देने पर जोर दिया जाएगा। नई एक्सप्रेस-वे सड़कों के निर्माण और परिवहन नेटवर्क के विस्तार से राज्य के भीतर और बाहर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की योजना भी इसमें शामिल है।

कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने पर है। कृषि रोड मैप को नई गति दी जाएगी, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इसके साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को और सुदृढ़ करने की योजना भी सात निश्चय-3 का अहम हिस्सा है। नए मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से राज्य के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना में शहरी विकास को भी खास महत्व दिया गया है। आधुनिक शहरी विस्तार, आधारभूत संरचना के निर्माण और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन को और प्रभावी बनाने, सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए भी इस योजना के तहत ठोस कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल आज मनपाओं और नपाओं को 2800 करोड़ रुपए की ग्रांट-सहायता राशि के चेक वितरित करेंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल कल यानी बुधवार, 17 दिसंबर, 2025 को दोपहर 3.00 बजे अहमदाबाद में राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2800 करोड़ रुपए की राशि के चेक वितरित करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2025 का वर्ष शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तब 2800 करोड़ रुपए की ग्रांट-सहायता की यह राशि राज्य के शहरी विकास को नई गति देगी।

अहमदाबाद के शैला इलाके में स्थित औडा ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई, शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला और महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

अहमदाबाद के स्कूलों और साबरमती जेल तक बम धमाके की धमकी, अमित शाह और लॉरेंस बिश्नोई का नाम शामिल

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में मंगलवार सुबह चार स्कूलों को बम धमाके की धमकी भरे ईमेल मिलने से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। ईमेल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी शामिल था। धमकी में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह धमाके स्कूलों से लेकर साबरमती जेल तक हो सकते हैं। धमकी मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने चारों स्कूलों का फुल-सुरक्षा चक्र बंद किया और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया।

धमकी प्राप्त करने वाले स्कूलों में जेबर स्कूल, महाराजा अग्रसेन स्कूल, DAV इंटरनेशनल विद्यालय और जायड्स विद्यालय शामिल हैं। पुलिस ने जांच के दौरान स्कूल परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई, लेकिन सुरक्षा कारणों से सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए और छात्रों तथा कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। अहमदाबाद शहर पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर शरद सिंघल ने कहा कि धमकी की गंभीरता को देखते हुए सभी उपाय किए गए हैं और साइबर टीम मामले की जांच कर रही है।

ईमेल की भाषा और संदर्भ से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे खालिस्तानी आतंकियों की ओर से भेजा गया है। धमकी में उल्लेख किया गया कि अमित शाह और लॉरेंस बिश्नोई को निशाना बनाया जाएगा। ईमेल में यह भी लिखा गया कि खालिस्तान रेफरेंडम के 900 दिन पूरे होने पर कनाडा में भारतीय सैनिकों द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराई गई थी और इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। ईमेल में हिंदू गुजराती और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने की बात भी कही गई थी।

पुलिस का कहना है कि ईमेल की जांच के लिए साइबर सेल और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। धमकी में अमित शाह और लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने के कारण इसे गंभीर माना जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई लंबे समय से गुजरात की हाईटेक और हाईप्रोफाइल साबरमती जेल में बंद हैं। सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से पहले ही कार्रवाई की जा सके।

अहमदाबाद प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध ईमेल या संदिग्ध वस्तु की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दें। उल्लेखनीय है कि शहर में पहले भी स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं, जिनमें एक बार एक महिला को पकड़ा गया था जिसने निजी कारणों से धमकी भेजी थी। इस बार की धमकी राष्ट्रीय और हाई-प्रोफाइल संदर्भों वाली होने के कारण इसे पहले से अधिक गंभीरता से लिया जा रहा है।

अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए चुना गया है, इसलिए शहर की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन और पुलिस बल ने स्कूलों के आसपास निगरानी बढ़ा दी है और छात्रों, शिक्षकों तथा स्टाफ की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। ईमेल की जांच अभी चल रही है और पुलिस ने कहा है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

अहमदाबाद में 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बेटी, पिता ने छलांग लगाकर किया बचाव, फायर ब्रिगेड ने 20 मिनट में निकाला

(जीएनएस)। अहमदाबाद। शहर के चंद्रलोडिया इलाके में स्थित एक जैन मंदिर के पास शुक्रवार रात को दिल दहलाने वाली घटना हुई। गजराज सोसाइटी में रहने वाले राजेशभाई सैनी की 19 साल की बेटी अंजलि सैनी खेलते-खेलते अचानक मंदिर के पास बने 60 फीट गहरे और पानी से भरे बोरवेल में गिर गई। गिरने की आवाज सुनते ही पिता राजेशभाई ने बिना देर किए अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद भी बोरवेल में छलांग लगा दी।

आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हुए और उन्होंने रस्सियों की मदद से दोनों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बोरवेल की गहराई और पानी की वजह से यह कोशिश नाकाम रही। स्थिति नाजुक थी और पिता-पुत्री डूबने के कगार पर थे। इसी दौरान फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और नवरंगपुरा फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। फायर ऑफिसर हितेश पटेल ने बताया कि टीम ने मिनी टैंकर और आवश्यक बचाव उपकरणों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

फायर ब्रिगेड के जवानों ने एक फायर फाइटर को रस्सी और बचाव उपकरणों के साथ बोरवेल में उतारा और एक-एक करके पिता-पुत्री को सुरक्षित बाहर निकाला। सबसे पहले बेटी अंजलि को बाहर निकाला गया, उसके बाद पिता राजेशभाई को। इस पूरे अभियान में लगभग 20 मिनट का समय लगा। फायर ऑफिसर ने बताया कि बोरवेल लगभग 50-60 फीट गहरा और पांच फीट चौड़ा था। सूचना मिलने में थोड़ी देर हो गई थी, और तब तक पिता-पुत्री करीब 30 मिनट तक बोरवेल में फंसे रहे।

बचाव के बाद पिता-पुत्री को तुरंत 108 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी से सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने भी घटना की जानकारी प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने आसपास के लोगों को हिला दिया और फायर ब्रिगेड की तत्परता और कुशलता की व्यापक सराहना की जा रही है।

राजेशभाई सैनी की बेटी अंजलि और उनके पिता दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि पुराने और खुली बोरवेलों के पास बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है। पड़ोसियों ने बताया कि यह बोरवेल पुराना था और अक्सर वहां लोग खेलकूद के दौरान पास से गुजरते थे, लेकिन किसी ने इसे ढकने या सुरक्षित करने की व्यवस्था नहीं की थी। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए आसपास के सभी बोरवेलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।

सीमाओं पर सख्ती का असर, 11 वर्षों में 23,926 घुसपैठिए दबोचे गए, भारत-चीन सीमा पूरी तरह सुरक्षित

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर संसद में सरकार ने एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। सरकार के मुताबिक वर्ष 2014 से अब तक देश की अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कुल 23,926 घुसपैठियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इतने लंबे समय में भारत-चीन सीमा पर घुसपैठ का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। यह जानकारी लोकसभा में लिखित जवाब के जरिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी, जिसने सीमा सुरक्षा को लेकर सरकार के दावों को मजबूती दी है।

सरकार के अनुसार, भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन उत्तरी सीमा यानी चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर घुसपैठ का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। यह तथ्य ऐसे समय सामने आया है, जब चीन सीमा को लेकर अक्सर राजनीतिक और रणनीतिक बहस होती रहती है। गृह राज्य मंत्री ने यह जानकारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया और शर्मिला सरकार के सवाल के जवाब में दी।

आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर पकड़े गए हैं। 2014 से 2024 के बीच भारत-बांग्लादेश, भारत-म्यांमार, भारत-पाकिस्तान और भारत-नेपाल-भूटान सीमाओं पर कुल 20,806 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। वहीं केवल जनवरी से नवंबर 2025 के बीच ही इन सीमाओं पर 3,120 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। इस तरह कुल आंकड़ा 23,926 तक पहुंच गया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2014 से अब तक भारत-बांग्लादेश सीमा पर सबसे ज्यादा 18,851 घुसपैठिए पकड़े गए हैं। इसके बाद भारत-म्यांमार सीमा पर 1,165, भारत-पाकिस्तान सीमा पर 556 और भारत-नेपाल-भूटान सीमाओं पर 234 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि भारत की पूर्वी सीमा, खासकर बांग्लादेश से लगी सीमा, घुसपैठ के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील बनी हुई है।

साल 2025 के जनवरी से नवंबर तक के आंकड़े भी इसी रुझान की पुष्टि करते हैं। इस अवधि में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 2,556 घुसपैठिए पकड़े गए, जबकि भारत-म्यांमार सीमा पर 437, भारत-पाकिस्तान सीमा पर 49 और भारत-नेपाल-भूटान सीमाओं पर 78 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे समय में भारत-चीन सीमा पर घुसपैठ का एक भी मामला सामने नहीं आया है।

सरकार का कहना है कि सीमा सुरक्षा बलों की सतर्कता, तकनीकी निगरानी, बाड़बंदी, गश्त और खुफिया तंत्र की मजबूती के कारण घुसपैठ पर काफी हद तक अंकुश लगाया गया है। खासकर भारत-चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई गई है। हालांकि, बांग्लादेश और म्यांमार सीमा से लगातार सामने आ रहे मामलों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और वहां निगरानी और कड़ी की जा रही है।

संसद में पेश किए गए ये आंकड़े न केवल देश की सीमा सुरक्षा की मौजूदा तस्वीर पेश करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि अलग-अलग सीमाओं पर चुनौतियां अलग-अलग प्रकृति की हैं। जहां एक ओर चीन सीमा पर शून्य घुसपैठ का दावा किया गया है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी सीमाओं पर घुसपैठ की समस्या अब भी सरकार और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

कोल इंडिया को मिला नया नेतृत्व, बी. साईराम ने संभाली देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी की कमान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की ऊर्जा सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को नया नेतृत्व मिल गया है। बी. साईराम ने कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कोल इंडिया ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी गई आधिकारिक सूचना में इसकी पुष्टि की। बी. साईराम इससे पहले नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उनके पास कोयला क्षेत्र में लंबा प्रशासनिक और तकनीकी अनुभव रहा है।

कंपनी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बी. साईराम ने कोयला विभाग के अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा का स्थान लिया है, जो प्रधानमंत्री प्रसाद की सेवानिवृत्ति के बाद एक नवंबर से कोल इंडिया के अंतरिम चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे। बी. साईराम ने 15 दिसंबर से औपचारिक रूप से कोल इंडिया के चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। ऐसे समय में उनका कार्यभार ग्रहण करना अहम माना जा रहा है, जब देश में बिजली और औद्योगिक गतिविधियों की बढ़ती मांग के कारण कोयले की खपत लगातार बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि देश के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है, जिससे कंपनी की भूमिका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

पदभार संभालने के बाद बी. साईराम ने कहा कि उनका प्रमुख फोकस ऑपरेशनल एक्सीलेंस हासिल करने पर रहेगा और कोयला उत्पादन, आपूर्ति तथा उत्पादकता को नई गति दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बढ़ती घरेलू ऊर्जा मांग को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया के लिए तय किए गए रिकॉर्ड उत्पादन लक्ष्यों को समय पर पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों से किसी भी तरह का समझौता न करने पर जोर दिया।

कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद बी. साईराम ने कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों के चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशकों के साथ एक वर्चुअल बैठक भी की। इस बैठक में चालू वित्त वर्ष के कोयला उत्पादन लक्ष्यों की समीक्षा की गई और सभी इकाइयों से समन्वय के साथ लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया गया। बैठक में कंपनी के शीर्ष प्रबंधन की मौजूदगी रही, जिसमें निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन, निदेशक (वित्तपोषण) मुकेश चौधरी, निदेशक (वित्त) मुकेश अग्रवाल और निदेशक (तकनीकी) अच्युत घटक शामिल थे।

ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि बी. साईराम के नेतृत्व में कोल इंडिया उत्पादन क्षमता बढ़ाने, खदानों में आधुनिक तकनीक अपनाने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर और अधिक फोकस कर सकती है। ऐसे समय में जब देश आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, कोल इंडिया के नए चेयरमैन से यह उम्मीद की जा रही है कि वे कंपनी को न केवल उत्पादन के मोर्चे पर बल्कि सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और दक्षता के मामले में भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

माननीय विधायक श्री लक्ष्मणजी ठाकोर ने कलोल स्टेशन पर चार ट्रेनों के ठहराव का शुभारंभ किया

(जीएनएस)। माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में माननीय विधायक श्री लक्ष्मणजी पुंजाजी ठाकोर ने 16 दिसंबर 2025 को कलोल रेलवे स्टेशन पर वलसाड–वडनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस, जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस और मुजफ्फरपुर–साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर माननीय विधायक, कलोल श्री लक्ष्मणजी ठाकोर ने अपने संबोधन में कहा कि कलोल रेलवे स्टेशन पर

1. 20959/60 वलसाड–वडनगर–वलसाड इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कलोल को वलसाड, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद तथा वडनगर जैसे महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है।
2. 16507/08 जोधपुर–बेंगलुरु–जोधपुर एक्सप्रेस, जो कलोल को राजस्थान, महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ती है।
3. 15269/70 मुजफ्फरपुर–साबरमती–मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस, जो कलोल को बिहार सहित उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ती है और आम यात्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
4. 12215/16 दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस–दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीबरथ एक्सप्रेस, जो कलोल को देश की राजधानी दिल्ली तथा आर्थिक राजधानी मुंबई से सीधे जोड़ती है।

इन सभी ट्रेनों के ठहराव से कलोल एवं आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधी, सुलभ और समय की बचत करने वाली यात्रा सुविधा प्राप्त होगी। GIDC छत्राल में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी तथा उनको ट्रेन पकड़ने के लिए महेसाणा और अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही विद्यार्थियों, नौकरीपेशा वर्ग, व्यापारियों, किसानों तथा स्थानीय श्रमिकों को अन्य बड़े स्टेशनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा में होने वाला समय, श्रम और आर्थिक व्यय—तीनों में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके साथ ही व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

कलोल रेलवे स्टेशन का लगभग 44.22 करोड़ रु. की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कलोल स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त, सुरक्षित एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है।

कलोल स्टेशन पर 40 फीट चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जो स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों को जोड़ते हुए शहर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही, स्टेशन के पूर्वी छोर पर द्वितीय प्रवेश (सेकेंड एंट्री) भवन का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे कलोल के पूर्वी क्षेत्र के नागरिकों को टिकट बुकिंग, प्रतीक्षालय एवं अन्य यात्री सुविधाओं का सीधा लाभ प्राप्त होगा।

वर्तमान में कलोल स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 2,000 यात्री आवागमन करते हैं और 24 ट्रेनें यहां नियमित रूप से रुकती हैं। हैं। इन चार जोड़ी ट्रेनों के ठहराव के साथ कुल 32 ट्रेनों का ठहराव कलोल स्टेशन पर हो जाएगा।

इन चार ट्रेनों का कलोल स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान का समय निम्नानुसार रहेगा:

1. ट्रेन संख्या 20959/20960 वलसाड–वडनगर-वलसाड सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20959 वलसाड–वडनगर एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 11.37 बजे आगमन एवं 11.39 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 20960 वडनगर-वलसाड एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 18.15 बजे आगमन एवं 18.17 बजे प्रस्थान करेगी।

2. ट्रेन संख्या 12215/12216 दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12215 दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 22.41 बजे आगमन एवं 22.43 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 20.11 बजे आगमन एवं 20.13 बजे प्रस्थान करेगी।

3. ट्रेन संख्या 16507/16508 जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 16507 जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 12.55 बजे आगमन एवं 12.57 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 16508 केएसआर बेंगलुरु-जोधपुर एक्सप्रेस 17 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 06.19 बजे आगमन एवं 06.21 बजे प्रस्थान करेगी।

4. ट्रेन संख्या 15269/15270 मुजफ्फरपुर–साबरमती साप्ताहिक जनसाधारण एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 15269 मुजफ्फरपुर–साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस 20 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 05.53 बजे आगमन एवं 05.55 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस 20 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 18.28 बजे आगमन एवं 18.30 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अर्धसैनिक बलों में बढ़ता मानसिक दबाव, 11 साल में 23 हजार से ज्यादा जवानों ने छोड़ी वर्दी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ माने जाने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में मानसिक तनाव और कार्यदबाव की तस्वीर चिंताजनक होती जा रही है। पिछले 11 वर्षों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से 23,360 से अधिक जवानों का इस्तीफा देना और बीते तीन वर्षों में 438 आत्महत्याओं के मामले सामने आना इस गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। संसद में पेश किए गए आंकड़ों से साफ है कि वर्दी के पीछे छिपा दबाव अब जवानों के धैर्य की सीमा तोड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 से अब तक सबसे अधिक इस्तीफे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से सामने आए हैं, जहां 7,493 जवानों ने नौकरी छोड़ी। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) से 7,456 और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से 4,137 कर्मियों ने इस्तीफा दिया। अन्य बलों को मिलाकर कुल संख्या 23 हजार के पार पहुंच चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि केवल वर्ष 2025 में ही अब तक 3,077 जवानों ने इस्तीफा दे दिया है, जिनमें 1,157 अकेले बीएसएफ के हैं।

इस्तीफों के साथ-साथ आत्महत्याओं के आंकड़े भी उतने ही गंभीर हैं। बीते तीन वर्षों में सीएपीएफ में आत्महत्या के कुल 438 मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2023 में 157 जवानों ने अपनी जान ली, 2024 में यह संख्या 148 रही, जबकि 2025 में अब तक 133 आत्महत्याएं सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा आपसी हिंसा की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही हैं। 2023 में आपसी हत्या के दो, 2024 में एक और 2025 में चार मामले दर्ज किए गए हैं, जो बलों के भीतर बढ़ते तनाव को दर्शाते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया कि आत्महत्या के सबसे अधिक मामले सीआरपीएफ में दर्ज किए गए हैं, जहां तीन वर्षों में 159 जवानों ने जान दी। इसके बाद बीएसएफ में 120 और सीआईएसएफ में 60 आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं। इन आंकड़ों ने बलों में तैनाती की परिस्थितियों, लंबी ड्यूटी, पारिवारिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सरकार का कहना है कि सीएपीएफ के जवान सामान्य तौर पर आठ घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, हालांकि ऑपरेशनल जरूरतों के चलते ड्यूटी के घंटे बढ़ भी सकते हैं। बटालियन स्तर पर प्रशिक्षण, विश्राम और अवकाश की व्यवस्था की जाती है ताकि कर्मियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। फील्ड में तैनात जवानों को हर साल 75 दिनों का अवकाश देने का प्रावधान है, जिसमें 60 दिन का अर्जित अवकाश और 15 दिन का आकस्मिक अवकाश शामिल है। मंत्रालय का दावा है कि अधिकतम छुट्टियां दिलाने के प्रयास किए जाते हैं।

इसके बावजूद लगातार बढ़ते इस्तीफे और आत्महत्याओं के आंकड़े बताते हैं कि जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। लंबे समय तक परिवार से दूर रहना, संवेदनशील इलाकों में तैनाती, लगातार तनावपूर्ण माहौल और सीमित मानसिक स्वास्थ्य सहयोग जवानों को भीतर से तोड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते मानसिक स्वास्थ्य, काउंसलिंग और कार्य-जीवन संतुलन पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट आने वाले वर्षों में और गहराता जा सकता है। देश की सुरक्षा में दिन-रात खड़े रहने वाले इन जवानों की मानसिक मजबूती को प्राथमिकता देना अब सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन चुका है।